



Drishti IAS



करेंट अफेयर्स

उत्तराखण्ड

जून

2023

(संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009

Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501

Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

उत्तराखंड

➤ नवीन चकराता टाउनशिप बसाए जाने को कैबिनेट की हरी झंडी	3
➤ प्रदेश में छात्रों को स्कॉलरशिप का तोहफा	4
➤ मुख्यमंत्री ने 'गंगा के प्रहरी' एवं 'स्वच्छता ही सेवा' पुस्तकों का किया विमोचन	4
➤ एकल महिला-पुरुष सरकारी कर्मचारी को भी मिलेगी चाइल्ड केयर लीव	5
➤ मसूरी के कैंप्टीफाल में बनेगी उत्तराखंड की पहली टनल पार्किंग	5
➤ एशिया और वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के लिये उत्तराखंड की प्रतिभा थपलियाल का चयन	6
➤ उत्तराखंड में बनेंगे ड्रोन कॉरिडोर	7
➤ देहरादून में डाक विभाग की नई शुरुआत	8
➤ प्रदेश में पाँच महीने में 12 बाघ-बाघियों की मौत	8
➤ राज्य के चार मैदानी जिलों में बनेंगे 50-50 किमी. के साइकिल ट्रैक	9
➤ प्रदेश में दो नए शहर बसाने को केंद्र ने दी मंजूरी	9
➤ उत्तराखंड के दो मंदिरों में लागू हुआ ड्रेस कोड	10
➤ एनडीए और सीडीएस प्रारंभिक परीक्षा में चयन पर अब एक लाख रुपए देगी उत्तराखंड सरकार	11
➤ इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर के लिये सिडकुल और केंद्र सरकार के बीच जल्द होगा अनुबंध	12
➤ भारत-मालदीव का संयुक्त सैन्य अभ्यास 'एक्स एकुवेरिन' चौबटिया में शुरू हुआ	12
➤ प्रो. जेएमएस राणा बने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष	14
➤ नैनीसैनी एयरपोर्ट को जारी हुआ एरोड्रम लाइसेंस	14
➤ डेयरी विकास के लिये मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान	14
➤ उत्तराखंड में मेडिकल छात्रों को डिजी लॉकर से मिलेंगी डिग्रियाँ	15
➤ प्रदेश के खेल प्रशिक्षकों का मानदेय 15 हजार से बढ़ाकर 48 हजार करने की तैयारी	16
➤ प्रदेश में होगा आपदा प्रबंधन पर विश्व कॉन्ग्रेस का आयोजन	17
➤ प्रदेश की आठ शिखरों को रक्षामंत्री ने किया सम्मानित	18
➤ मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के नए पटेल भवन का किया उद्घाटन	19
➤ प्रदेश के लिये ओडिशा में लगेगा कोयले से बिजली का प्लांट	19
➤ प्रदेश में हर वाइब्रेंट विलेज में बनेगा हेलीपैड	20
➤ राष्ट्रपति ने सैन्य नर्सिंग सेवा की मेजर जनरल स्मिता देवरानी और ब्रिगेडियर अमिता देवरानी को राष्ट्रीय फ्लोरेस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया	21
➤ मुख्यमंत्री धामी ने किया करपात्री महाराज वेदशास्त्र अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण	23
➤ उत्तराखंड मल्टी हार्जर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम	23
➤ उत्तराखंड में साल के बीज लाएंगे समृद्धि, वनोपज में जुड़ा नया अध्याय	24
➤ नशा मुक्ति केंद्रों के संचालन लिये बनेगा एक्ट, केंद्र सरकार ने दी अनुमति	25
➤ प्रदेश में अब इजराइली कृषि तकनीक से होगी बागवानी	25
➤ टिहरी गढ़वाल में जी-20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक संपन्न	26
➤ प्रदेश के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्थापित होंगे वेदर स्टेशन	27
➤ प्रदेश में दो नए शहरों को बसाने का रास्ता साफ	28

उत्तराखंड

नवीन चकराता टाउनशिप बसाए जाने को कैबिनेट की हरी झंडी

चर्चा में क्यों ?

31 मई, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड कैबिनेट ने देहरादून जिले के नवीन चकराता टाउनशिप को बसाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- पुरोड़ी से लेकर लखवाड़ यमुना पुल तक का क्षेत्र टाउनशिप में शामिल किया जाएगा। इस बहु प्रतीक्षित टाउनशिप का निर्माण मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) करेगा।
- विदित है कि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल ने 6 नवंबर, 1997 में नवीन चकराता का शिलान्यास किया था। उनके ही प्रयासों से 26 नवंबर, 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने पूर्व कार्यकाल में नवीन चकराता टाउनशिप को बसाए जाने की घोषणा की थी।
- टाउनशिप में पुरोड़ी, रामताल गार्डन, बिरमोऊ कांडी, सजियाना, माख्ठी पोखरी, चौरानी डांडा, बैराटखाई, शिखाई डांडा, चौरी डांडा, पांचोई डांडा, वायधर, गांगरौ डांडा, ग्यावा डांडा, चिटाड़ा डांडा, श्यामधर, झुल्का डांडा, नागथात, टिकरथात, बानीथात, ड्युंडीलानी, देशगाड़, पिपाया, मटियाणा, जखोड़, सणिया आदि क्षेत्र टाउनशिप के अधिकार क्षेत्र में आएंगे, जबकि कालसी तहसील के 32 और चकराता के 8 गाँव आंशिक रूप से टाउनशिप का हिस्सा बनेंगे।
- टाउनशिप बनने से क्षेत्र के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में चकराता छावनी क्षेत्र में पाबंदी के चलते सीमित संख्या में होटल और व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं। पर्यटन को बढ़ावा मिलने से रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।
- जनजातीय क्षेत्र का दर्जा मिलने के बाद यह जौनसार बावर को मिलने वाला दूसरा बड़ा तोहफा है। टाउनशिप के बसने से जनजातीय क्षेत्र विकास के नए आयाम को छूएगा।



प्रदेश में छात्रों को स्कॉलरशिप का तोहफा

चर्चा में क्यों ?

31 मई, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

प्रमुख बिंदु

- इसके अंतर्गत सरकारी विश्वविद्यालयों और सरकारी डिग्री कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी।
- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के तहत ग्रेजुएशन में हर कॉलेज के हर संकाय में प्रथम आने वालों को 3000 रुपए, द्वितीय स्थान पर आने वाले को 2000 रुपए और तीसरे स्थान पर आने वाले को 1000 रुपए महीना स्कॉलरशिप दी जाएगी।
- पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रथम आने वाले को 5,000 रुपए दूसरे स्थान पर रहने वाले को 3000 रुपए और तीसरे स्थान पर आने वाले को 2000 रुपए महीना स्कॉलरशिप मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने 'गंगा के प्रहरी' एवं 'स्वच्छता ही सेवा' पुस्तकों का किया विमोचन

चर्चा में क्यों ?

31 मई, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के युवा साहित्यकार ललित शौर्य की पुस्तकों 'गंगा के प्रहरी' एवं 'स्वच्छता ही सेवा' का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने पुस्तकों को नदी संरक्षण एवं स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता के लिये लाभदायी बताते हुए कहा कि 'गंगा के प्रहरी' पुस्तक में कहानियों के माध्यम से नदियों के बारे में जानकारी के साथ नदियों की स्वच्छता के बारे में बताया गया है।
- वहीं, 'स्वच्छता ही सेवा' पुस्तक में स्वच्छता से संबंधित कहानियाँ स्वच्छता के साथ स्वच्छ भारत अभियान को जन-जन तक पहुँचाने में मददगार होगी।



एकल महिला-पुरुष सरकारी कर्मचारी को भी मिलेगी चाइल्ड केयर लीव

चर्चा में क्यों ?

1 जून, 2023 को उत्तराखंड के वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने प्रदेश के एकल महिला एवं पुरुष अभिभावक कर्मचारियों को बाल्य देखभाल अवकाश (चाइल्ड केयर लीव) देने के प्रस्ताव के संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

- एकल पुरुष अभिभावक में वे सभी कर्मचारी आएंगे जो अविवाहित या विधुर या तलाकशुदा हैं और जिनके एक बच्चे की जिम्मेदारी अकेले उनके कंधों पर है।
- जारी आदेश के मुताबिक, राज्य सरकार की महिला कर्मचारी व महिला-पुरुष एकल कर्मचारी संतान की बीमारी अथवा परीक्षा आदि के दौरान देखभाल के लिये संपूर्ण सेवाकाल में दो वर्ष यानी 730 दिन का बाल्य देखभाल अवकाश ले सकेंगे।
- यह अवकाश 18 वर्ष की आयु तक केवल दो बड़े जीवित बच्चों के लिये मान्य होगा। 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग बच्चों के मामले में आयु सीमा का कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
- यह अवकाश उपार्जित अवकाश की तरह स्वीकृत किया जाएगा और इसी की तर्ज पर इसका खाता रखा जाएगा। इस अवकाश के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश बाल्य देखभाल अवकाश में शामिल माने जाएंगे।
- जनहित और प्रशासकीय कार्यों के लिये नियुक्त प्राधिकारी किसी कर्मचारी को एक बार में पाँच दिनों से कम व 120 दिनों से अधिक अवधि का अवकाश मंजूर नहीं करेगा।
- एकल महिला सरकारी कर्मचारी को एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम छह बार व अन्य पात्र महिला-पुरुष कर्मचारी को एक कैलेंडर वर्ष में तीन बार अवकाश मिलेगा। 365 दिन के अवकाश का उन्हें पूरा वेतन मिलेगा। अगले 365 दिनों में उन्हें मंजूर अवकाश का 80 प्रतिशत ही वेतन दिया जाएगा।
- कई विभागों के राजकीय व सहायता प्राप्त शिक्षण, प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के पात्र महिला पुरुष सरकारी शिक्षकों (यूजीसी, सीएसआईआर व आईसीएआर के पदों को छोड़कर) व सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं को शिक्षणतर पात्र कर्मचारी को भी अवकाश मिलेगा।
- परिवीक्षाकाल (प्रोबेशन) में रहने के दौरान कर्मचारी बाल्य देखभाल अवकाश के हकदार नहीं होंगे, लेकिन जिन विभागों की सेवा नियमावली में प्रोबेशन पीरियड के दौरान बाल्य देखभाल अवकाश की व्यवस्था है, वहाँ यह तीन महीने से अधिक नहीं दिया जा सकेगा।
- विशेष परिस्थितियों में नियुक्ति प्राधिकारी गुण-दोष के आधार पर कम से कम अवधि का बाल्य देखभाल अवकाश मंजूर करने पर भी विचार कर सकते हैं।

मसूरी के कैंप्टीफाल में बनेगी उत्तराखंड की पहली टनल पार्किंग

चर्चा में क्यों ?

4 जून, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में पहली टनल पार्किंग कैंप्टीफाल में टिहरी-कैंप्टीफाल मसूरी, मसीही मसूरी रोड के सामने बनाई जाएगी, जिसकी 120 करोड़ की डीपीआर तैयार हो चुकी है।

प्रमुख बिंदु

- राज्य में पार्किंग की समस्या के समाधान के लिये 12 शहरों में पहाड़ में टनल पार्किंग बनाई जानी हैं। इनमें पौड़ी में दो, टिहरी में छह, उत्तरकाशी में दो और नैनीताल में दो पार्किंग शामिल हैं।
- इस पार्किंग में 400 वाहनों को पार्क करने की सुविधा मिलेगी।
- यहाँ बनेगी टनल पार्किंग :
 - ◆ पौड़ी-लक्ष्मण झूला और देवप्रयाग रेलवे स्टेशन के पास सौड़।

- ◆ ओल्ड टिहरी रोड कूड़ाघर के सामने (चंबा), नैनबाग धनोल्टी, छिलेड़ी गाँव, तेगड़ बाजार और थत्यूड बाजार, मेन बाजार।
- ◆ उत्तरकाशी-गंगोत्री और गंगनानी।
- ◆ नैनीताल-भवाली रोड पर कैंट बोर्ड की जमीन और नेशनल ऑब्जर्वेटरी के पास पहला मोड़।
- जिन पर्वतीय जिलों में पार्किंग के लिये बड़ा मैदान उपलब्ध नहीं है, वहाँ पहाड़ों के भीतर ही टनल से पार्किंग का काम लिया जाएगा। ये पार्किंग ऐसी बनाई जाएगी कि एक तरफ से वाहन पार्किंग के लिये घुसेगा और दूसरी सड़क पर बाहर निकल जाएगा।

एशिया और वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के लिये उत्तराखंड की प्रतिभा थपलियाल का चयन

चर्चा में क्यों ?

4 जून, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार नेपाल और साउथ कोरिया में होने वाली एशिया और वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के लिये गोवा में इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन की ओर से आयोजित ट्रायल में पूरे देश से सिर्फ उत्तराखंड की प्रतिभा थपलियाल का चयन हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- गोवा में इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन की ओर से आयोजित ट्रायल में देशभर की करीब 23 महिला बॉडी बिल्डरों ने प्रतिभाग किया। इनमें से सिर्फ प्रतिभा थपलियाल का चयन किया गया।
- विदित है कि 6 से 12 सितंबर तक नेपाल की राजधानी काठमांडू में एशिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन होना है। जबकि, 30 अक्टूबर से 6 नवंबर तक साउथ कोरिया की राजधानी सिओल में वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता होनी है।
- गौरतलब है कि राज्य के पौड़ी के यमकेश्वर ब्लॉक की मूल निवासी प्रतिभा उत्तराखंड की पहली महिला बॉडी बिल्डर हैं। इससे पहले भी उन्होंने कई प्रतियोगिताओं में जीत हासिल कर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है।
- इससे पहले वह वॉलीबॉल में बतौर कप्तान उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और पाँच बार नॉर्थ जोन से खेल चुकी हैं। इसके अलावा वह चार बार क्रिकेट में भी ऑल इंडिया स्तर पर खेल चुकी हैं।



उत्तराखंड में बनेंगे ड्रोन कॉरिडोर

चर्चा में क्यों ?

5 जून, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में ड्रोन संचालन को बढ़ावा देने के लिये कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इसके लिये सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) ने ड्रोन संचालन व निर्माण कंपनियों से प्रस्ताव मांगें हैं।

प्रमुख बिंदु

- आईटीडीए की निदेशक नितिका खंडेलवाल ने बताया कि पिछले दिनों ड्रोन नीति बनाने के दौरान सभी हितधारकों की बैठक हुई थी। इसमें हितधारकों विशेषकर ड्रोन निर्माता व संचालकों से संभावित ड्रोन कॉरिडोर का प्रस्ताव मांगा गया है।
- उन्होंने बताया कि यह प्रस्ताव आने के बाद राज्य के हवाई नक्शे के हिसाब से इसका अध्ययन किया जाएगा। फिर उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) के माध्यम से नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को प्रस्ताव भेजा जाएगा।
- डीजीसीए से अनुमति मिलने के बाद राज्य में ड्रोन के कॉरिडोर तय हो जाएंगे। सभी जिलों में ड्रोन संचालन के लिये जो कॉरिडोर बनेंगे, उन्हें आपस में लिंक किया जाएगा। इसके बाद प्रदेश में ड्रोन के समर्पित रास्तों का पूरा नेटवर्क तैयार हो जाएगा। नियम को तोड़ने वालों पर भविष्य में कार्रवाई भी हो सकेगी।
- ड्रोन कॉरिडोर बनाने के पीछे एक मकसद यह भी है कि इससे ऐसे रास्ते तैयार किये जाएंगे, जो हवाई सेवाओं को बाधित न करें। वहीं, सीमांत प्रदेश होने के नाते तमाम प्रतिबंधित क्षेत्रों को भी सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
- ज्ञातव्य है कि वर्तमान में प्रदेश में उत्तरकाशी से दून या अन्य जगहों पर ड्रोन संचालन का कोई समर्पित कॉरिडोर नहीं है, जिससे कई ड्रोन को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इससे अधिक समय लगने और ड्रोन की बैटरी भी जल्द खत्म होने का खतरा है। ड्रोन कॉरिडोर के बन जाने से उड़ान का समय तो कम होगा ही, उसकी बैटरी भी लंबी दूरी की उड़ान में मदद करेगी।
- ड्रोन के क्षेत्र में तेजी से हो रहे विकास के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार जल्द ही ड्रोन नीति लाने जा रही है। आईटीडीए ने इसका ड्राफ्ट शासन को भेजा है। इसके तहत ड्रोन संचालन से लेकर ड्रोन की खरीद तक के सभी प्रावधान किये जाएंगे।



देहरादून में डाक विभाग की नई शुरुआत

चर्चा में क्यों ?

6 जून, 2023 को उत्तराखंड के डाक सेवा निदेशक अनुसूया प्रसाद चमोला ने बताया कि डाक विभाग अब स्पीड पोस्ट व पार्सल को हवाई सेवा के माध्यम से दिल्ली पहुँचा रहा है। इसके लिये डाक विभाग ने एक हवाई कंपनी के साथ करार किया है। अभी तक यह काम ट्रेन के जरिये किया जाता था।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि डाक विभाग ने रेलवे के साथ मिलकर एक विशेष रेल मेल सर्विस (आरएमएस) शुरू की थी। इसके तहत देहरादून समेत पर्वतीय जिलों से दून स्थित मुख्य डाकघर में आने वाले स्पीड पोस्ट व पार्सल को दो ट्रेनों (मसूरी एक्सप्रेस/योगा एक्सप्रेस) के जरिये देहरादून से दिल्ली पहुँचाया जाता था। लेकिन, मसूरी एक्सप्रेस को दिल्ली पहुँचने में लंबा समय लगता है।
- इसे देखते हुए आरएमएस से मसूरी एक्सप्रेस को हटा दिया गया है। इसके बदले अब डाक विभाग एक हवाई कंपनी की फ्लाइट से स्पीड पोस्ट व पार्सल भेज रहा है। हालाँकि हरिद्वार से चलने वाली योगा एक्सप्रेस ट्रेन से स्पीड पोस्ट व पार्सल भेजे जा रहे हैं, लेकिन विभाग इस ट्रेन के स्थान पर भी दूसरी हवाई कंपनी का विकल्प तलाश रहा है।
- विदित है कि अभी फिलहाल उन पार्सल और डाक को हवाई सेवा के जरिये दिल्ली पहुँचाया जा रहा है जो महत्वपूर्ण हैं। जिसके चलते सप्ताह भर में पहुँचने वाली स्पीड पोस्ट व पार्सल कुछ ही दिन में लोगों तक पहुँच जा रही है। जबकि अन्य स्पीड पोस्ट व पार्सल को विभागीय वाहन से हरिद्वार पहुँचाने के बाद ट्रेन से अहमदाबाद पहुँचाया जा रहा है।
- जीपीओ में दिनभर में सौ से ज्यादा पार्सल बुक किये जा रहे हैं। इनमें वे भी पार्सल शामिल हैं जो विदेश जाने वाले होते हैं। जबकि दून समेत पर्वतीय इलाकों के अन्य डाक घरों में देशभर के लिये बुक होने वाले पार्सल भी देर शाम को जीपीओ ही आते हैं।

प्रदेश में पाँच महीने में 12 बाघ-बाघियों की मौत

चर्चा में क्यों ?

5 जून, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार देशभर में बाघों के संरक्षण के तहत किये जा रहे प्रयासों के बीच उत्तराखंड में लगातार बाघों की मौत हो रही है। यहाँ बीते पाँच महीनों में 12 बाघ-बाघियों की मौत हो चुकी है।

प्रमुख बिंदु

- उत्तराखंड वन विभाग के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक डॉ. समीर सिन्हा ने बताया कि प्रदेश में इस साल अभी तक 12 बाघों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा मौतें सेंट्रल तराई क्षेत्र में हुई हैं। ज्यादातर मौतें आपसी संघर्ष या किसी दुर्घटना में हुई हैं। मुख्य वन संरक्षक कुमाऊँ को विस्तृत जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।
- विदित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष अप्रैल में देश में बाघ गणना-2022 के आँकड़े जारी किये थे। उसमें पिछले चार वर्षों में बाघों की संख्या में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई गई है। देशभर में बाघों की संख्या करीब 3167 बताई गई है।
- वर्ष 2018 की गणना के अनुसार उत्तराखंड में बाघों की संख्या 442 है। अभी राज्यवार आँकड़े जारी नहीं किये गए हैं, लेकिन उत्तराखंड वन विभाग के अधिकारी इन्हीं आँकड़ों के आधार पर प्रदेश में बाघों की संख्या बढ़ने की संभावना बता रहे हैं। इसके उलट जिस तेजी से बाघों की मौत हो रही है, उससे तस्वीर का रंग धुंधला भी हो सकता है।
- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की ओर से जारी आँकड़ों के अनुसार, देशभर में इस साल बीते पाँच महीनों में कुल 76 बाघों की मौत हुई है। इनमें 12 बाघ केवल उत्तराखंड में मारे गए। उत्तराखंड में इस साल बाघ की पहली मौत का मामला जनवरी में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सामने आया था। उसके बाद फरवरी में तीन बाघ नैनीताल और रामनगर में मृत पाए गए। फिर मार्च में दो बाघ चकराता रेंज हल्द्वानी और रामनगर डिविजन में मारे गए।
- अप्रैल में कॉर्बेट की डेला रेंज में एक बाघ मृत पाया गया। मई में दो बाघ कालागढ़ डिविजन और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में मारे गए, जबकि तीन बाघों की मौत का आँकड़ा अभी तक वेबसाइट पर अपडेट नहीं किया गया है। बाघों की मौत के कारण अलग-अलग हैं। वर्ष 2022 में 12 महीने में नौ बाघों की मौत दर्ज की गई थी।
- गौरतलब है कि वर्ष 2001 से मई 2023 तक उत्तराखंड में मृत बाघों की संख्या 181 है।



राज्य के चार मैदानी ज़िलों में बनेंगे 50-50 किमी. के साइकिल ट्रैक

चर्चा में क्यों ?

5 जून, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगरीय क्षेत्रों को वाहनों के बढ़ते दबाव और प्रदूषण से बचाने के लिये राज्य के चार मैदानी जिलों में 50-50 किमी. का साइकिल ट्रैक बनाए जाने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- लोगों की सुविधा के मद्देनजर राज्य के देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर और नैनीताल में 50-50 किमी. के साइकिल ट्रैक बनाए जाएंगे।
- इसके अलावा मुख्यमंत्री ने राज्य के नौ पर्वतीय जिलों में भी साइकिल ट्रैक बनाए जाने की संभावना तलाशने के निर्देश दिये।
- मुख्यमंत्री ने पर्यावरण दिवस पर राज्य में पारंपरिक जल स्रोतों और नदियों को सूखने से बचाने और उन्हें नया जीवन देने के उद्देश्य से 'स्प्रिंग व रिवर रिजुवनेशन बोर्ड' बनाए जाने का भी एलान किया।
- इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सभी 13 जिलों में स्वच्छता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली एक-एक ग्राम पंचायत को पुरस्कृत किया जाएगा।

प्रदेश में दो नए शहर बसाने को केंद्र ने दी मंजूरी

चर्चा में क्यों ?

7 जून, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में काशीपुर व डोईवाला के निकट दो नए शहर बसाने को केंद्र सरकार ने प्रारंभिक तौर पर मंजूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- उत्तराखंड आवास विभाग ने केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में सर्वसुविधा संपन्न शहर का प्रस्तुतीकरण दिया था, जिस पर सहमति जताते हुए जल्द ही दोनों टाउनशिप का निरीक्षण करने के लिये केंद्र की टीम उत्तराखंड पहुँचेगी।
- गौरतलब है कि आवास विभाग प्रदेश में आठ नए शहरों को बसाने की योजना पर काम कर रहा है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र से इस संबंध में अनुरोध करते हुए 1100 करोड़ का प्रस्ताव दिया था।
- इसके तहत आवास विभाग ने दो शहरों का प्रस्ताव तैयार किया था और केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को भेज दिया था। इनमें एक शहर काशीपुर में पराग फार्म की भूमि पर इंडस्ट्रियल सिटी के नाम से 378.50 हेक्टेयर भूमि पर बनेगा।

- दूसरी टाउनशिप, डोईवाला के निकट दून-हरिद्वार हाईवे पर एयरो सिटी के नाम से बनेगी। इंटीग्रेटेड टाउनशिप के नाम से यह शहर 3080.8 भूमि पर बनाया जाएगा। इसमें 746.98 हेक्टेयर सरकारी भूमि और 2333.81 हेक्टेयर निजी भूमि होगी।
- इन सभी शहरों में आवास विभाग सुविधाएँ देगा। इनमें सड़क, सीवर से लेकर अत्याधुनिक शहरों जैसी सभी सुविधाएँ शामिल होंगी।
- टाउन प्लानिंग विभाग की मदद से इन शहरों का मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। इसी हिसाब से निजी सहभागिता से शहरों को बनाने का काम होगा। सरकार इनमें कुछ अपनी ज़मीनें भी देगी।

प्रस्तावित 8 शहर		
चिन्हित स्थान	कुल भूमि (हेक्टे.)	शहर का नाम
डोईवाला के निकट दून-हरिद्वार हाईवे	3080.8	इंटीग्रेटेड टाउनशिप
दून-पौंटा साहिब हाईवे पर छरबा, सहसपुर	1672.94	साइबर सिटी
आर्केडिया चाय बागान, देहरादून	719.7	न्यू देहरादून ट्विन सिटी
गौचर हवाई पट्टी के पास बमोथ गाँव	50.00	वेलनेस टाउनशिप
रामनगर शहर के पास	4365	टूरिज्म टाउनशिप
गोलापार के निकट हल्द्वानी	2840.16	न्यू हल्द्वानी ट्विन सिटी
नैणीसैणी एयरपोर्ट के पास, पिथौरागढ़	77.00	फिल्म-एंटरटेनमेंट सिटी
पराग फार्म, किच्छा के पास	378.58	इंडस्ट्रियल टाउनशिप

उत्तराखंड के दो मंदिरों में लागू हुआ ड्रेस कोड

चर्चा में क्यों ?

8 जून, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में कांवड़ मेला शुरू होने से पहले राज्य के पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की ओर से हरिद्वार और ऋषिकेश जिलों के दो मंदिरों में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- जिन मंदिरों में ड्रेस कोड लागू किया गया है, वे हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर और ऋषिकेश के नीलकंठ महादेव मंदिर हैं। इनमें श्रद्धालुओं के लिये हाफ पैंट, फटी जींस, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट पहनकर आने वालों को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। मर्यादित कपड़े पहनकर आने वालों को ही मंदिर में प्रवेश कर दर्शन करने की अनुमति होगी।
- विदित है कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष एवं पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के सचिव श्रीमहंत रविंद्रपुरी महाराज ने कुछ दिन पहले इन दोनों मंदिरों में अमर्यादित कपड़े पहनकर आने वाले श्रद्धालुओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी।
- पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के सचिव ने बताया कि मंदिरों में मर्यादा को बनाए रखने के लिये कपड़ों की मर्यादा जरूरी है। दोनों मंदिरों में ड्रेस कोड को लागू करते हुए बैनर लगा दिये गए हैं। महिला हो या पुरुष अब अमर्यादित कपड़ों में इन मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। श्रद्धालुओं के शरीर 80 फीसदी तक ढके होने चाहिये।
- उन्होंने कहा कि शालीनतापूर्वक व संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये मंदिरों में साइन बोर्ड लगाए गए हैं।
- देश के अधिकांश मंदिर चाहे वह संतों के हों या फिर अन्य कमेटी, सरकार के ट्रस्ट के अधीन हों, सभी ने इस फैसले का स्वागत किया है।
- ज्ञातव्य है कि दक्षिण भारत के कई मंदिरों में ड्रेस कोड पहले से लागू है। उत्तराखंड तीर्थ स्थानों का प्रदेश है और यहाँ भी इसे लागू करने की जरूरत थी।



एनडीए और सीडीएस प्रारंभिक परीक्षा में चयन पर अब एक लाख रुपए देगी उत्तराखंड सरकार

चर्चा में क्यों ?

9 जून, 2023 को उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश के युवाओं के एनडीए (राष्ट्रीय रक्षा अकादमी) और सीडीएस (संयुक्त रक्षा सेवाएँ) की प्रारंभिक परीक्षा में चयन पर राज्य सरकार अब एक लाख रुपए देगी। इसके लिये विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- सेना में अफसर बनने का सपना लिये प्रदेश के युवाओं को राज्य सरकार मुफ्त कोचिंग के साथ ही आर्थिक और प्रोत्साहन राशि के रूप में एक लाख रुपए देने जा रही है। हालाँकि विभाग की ओर से अब तक इसके लिये 50 हजार रुपए दिये जा रहे हैं, लेकिन अब इस धनराशि को दोगुना किये जाने की तैयारी है।
- विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस योजना का लाभ उत्तराखंड के स्थायी एवं मूल निवासी उन छात्र-छात्राओं को मिलेगा, जिन्होंने 12वीं, स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षाएँ राज्य के शिक्षण संस्थाओं से पास की है।
- योजना के लाभ के लिये प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आने के एक महीने के भीतर आवेदन करना होगा। इस योजना का लाभ एक बार ही लिया जा सकेगा।
- विभाग के संयुक्त निदेशक एएस उनियाल ने बताया कि विभाग की ओर से मेधावी छात्र-छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की पहली बार मुफ्त कोचिंग कराई जाएगी। इसके लिये उत्तराखंड सहित दिल्ली, चंडीगढ़, हैदराबाद आदि राज्यों से एमओयू किया जाएगा। छात्रों को न सिर्फ एनडीए, सीडीएस और ओटीए बल्कि आईएएस और पीसीएस आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये भी तैयार किया जाएगा।
- मेधावी छात्रों के बेहतर भविष्य के लिये प्रारंभिक परीक्षा पास कर चुके छात्र-छात्राओं को सरकार मुख्य परीक्षा की तैयारी भी कराएगी।

नोट :

इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर के लिये सिडकुल और केंद्र सरकार के बीच जल्द होगा अनुबंध

चर्चा में क्यों ?

9 जून, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड का पहला इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर बनाने के लिये जल्द ही केंद्र सरकार और राज्य औद्योगिक विकास निगम (सिडकुल) के बीच अनुबंध किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- जानकारी के अनुसार राज्य के ऊधमसिंहनगर जिले के काशीपुर में 133 एकड़ जमीन पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर बनाया जाएगा। इसके लिये राज्य औद्योगिक विकास निगम (सिडकुल) ने डीपीआर तैयार कर ली है।
- क्लस्टर को बनाने में 115 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसमें 50 प्रतिशत राशि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से दी जाएगी। इसके लिये केंद्र ने क्लस्टर विकसित करने हेतु 56 करोड़ रुपए की स्वीकृत दे दी है।
- इस क्लस्टर के बनने के बाद इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण उद्योगों को जमीन के साथ सभी सुविधाएँ उपलब्ध होंगी, जिनमें लगभग 60 इलेक्ट्रॉनिक सामान, इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा, दूरसंचार, बिजली उपकरण बनाने वाली कंपनियों को प्लॉट दिये जाएंगे।
- क्लस्टर के अंदर उद्योगों के कर्मचारियों के लिये छात्रावास, वेयर हाउस, उपकरणों की जाँच के लिये लैब, फायर स्टेशन, चिकित्सा सुविधा भी मिलेगी।
- क्लस्टर में एंकर यूनिट के रूप में समृद्धि ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड लगभग 200 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इसके लिये कंपनी को आठ एकड़ जमीन का आवंटन किया गया है। क्लस्टर के बनने से इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में 700 करोड़ रुपये निवेश होने का अनुमान है।



भारत-मालदीव का संयुक्त सैन्य अभ्यास 'एक्स एकुवेरिन' चौबटिया में शुरू हुआ

चर्चा में क्यों ?

12 जून, 2023 को भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 11 से 24 जून 2023 तक उत्तराखंड के चौबटिया में होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास 'एक्स एकुवेरिन' के 12वें संस्करण का आगाज हो गया है।

प्रमुख बिंदु

- 'मित्र' अर्थ वाला एकुवेरिन, भारत और मालदीव में वैकल्पिक रूप से आयोजित होने वाला एक द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास है। भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल की एक पलटन जितनी क्षमता वाली टुकड़ी 14 दिनों तक चलने वाले इस अभ्यास में भाग लेगी।

- इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के कहे अनुसार काउंटर इंसर्जेंसी/आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन में इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना और संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों को अंजाम देना है। इसमें सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, सामरिक स्तर पर दोनों बलों के बीच समन्वय और सहयोग बढ़ाने पर ध्यान रहेगा।
- विदित है कि इस अभ्यास का 11वाँ संस्करण दिसंबर 2021 में मालदीव में आयोजित किया गया था।
- दोनों देशों के बीच ये रक्षा सहयोग, संयुक्त अभ्यास करने से लेकर रक्षा प्रशिक्षण और उपकरण आवश्यकताओं के लिये मालदीव की सहायता करने तक फैला हुआ है।
- दोनों देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और सैन्य सहयोग में बहुत नजदीकी और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। 'एक्स एक्चूवेरिन' दोनों देशों के बीच इन संबंधों को और मजबूत करने में मदद करेगा।



प्रो. जेएमएस राणा बने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष

चर्चा में क्यों ?

12 जून, 2023 को राज्य सरकार ने उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी आयोग के सदस्य प्रो. जगमोहन सिंह राणा को सौंप दी। कार्मिक विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिये।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. राकेश कुमार ने 10 जून को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से आयोग के अध्यक्ष की कुर्सी खाली पड़ी थी।
- डॉ. राकेश कुमार के इस्तीफे के बाद भर्तियों का विशेष अभियान चला रहे आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी शासन पर आ गई थी।
- राज्य शासन ने बिना देरी किये न केवल उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष का नाम तय किया बल्कि देर रात उत्तराखंड शासन के कार्मिक सचिव शैलेश बगोली ने आयोग के ही सदस्य डॉ. जेएमएस राणा को अपने पदीय दायित्वों के साथ ही अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपने का आदेश भी जारी कर दिया।



नैनीसैनी एयरपोर्ट को जारी हुआ एरोड्रम लाइसेंस

चर्चा में क्यों ?

13 जून, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने उत्तराखंड नागरिक उडन्यन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) के अंतर्गत राज्य के सीमांत जिले पिथौरागढ़ के नैनीसैनी एयरपोर्ट के लिये एरोड्रम लाइसेंस जारी कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

- एरोड्रम लाइसेंस मिलने से सीमांत जिले पिथौरागढ़ के नैनीसैनी एयरपोर्ट से अब नागरिक विमान भी उड़ान भर सकेंगे।
- विदित है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीसैनी एयरपोर्ट को एरोड्रम लाइसेंस देने का अनुरोध किया था।
- राज्य सरकार ने इस एयरपोर्ट के संचालन का जिम्मा वायुसेना को सौंप रखा है। अब वायु सेना के विमान के साथ इस एयरपोर्ट से नागरिकों की सुविधा के लिये व्यावसायिक विमान भी उड़ान भर सकेंगे।

डेयरी विकास के लिये मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान

चर्चा में क्यों ?

14 जून, 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून सचिवालय में गन्ना विकास, पशुपालन, डेयरी विकास व मत्स्य

विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक में राज्य में डेयरी विकास के लिये 600 बहुउद्देश्यी दुग्ध सहकारी समितियों की स्थापना करने के निर्देश दिये हैं।

प्रमुख बिंदु

- बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उच्च गुणवत्ता की ऊन देने वाली मेरीनो भेड़ों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिसके लिये जल्द ही ऑस्ट्रेलियन बीडर के साथ एमओयू किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ने राज्य में चारे की कमी के दृष्टिगत 20 फोडर एफपीओ के गठन, दुग्ध समितियों के क्लस्टर में 50 दुग्ध उत्पादक सेवा केंद्रों की स्थापना, 16 बदरी गाय ग्रोथ सेंटर की स्थापना के निर्देश दिये।
- उन्होंने दुग्ध समिति तथा दुग्ध संघ के कार्यों का ऑटोमेशन करने, पर्वतीय क्षेत्रों में सामुदायिक भूमि पर 10 लाख चारा पौधों का रोपण कर चारे की कमी की समस्या को हल करने, उत्तराखंड की समस्त दुग्ध समितियों तथा समस्त दुग्ध संघों को लाभ में लाने के लिये लक्ष्य निर्धारित कर कार्य करने के निर्देश दिये।
- गन्ना विकास विभाग को बाजपुर व किच्छा चीनी मिलों के आधुनिकीकरण, गन्ना बीज बदलाव, जीपीएस के माध्यम से गन्ना सर्वेक्षण का कार्य तथा प्रदेश में जैविक गन्ना उत्पादन को बढ़ावा देने के लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिये गए।
- उन्होंने मत्स्य पालन के लिये 468 हेक्टेयर नए जल क्षेत्रों के विस्तार, 863 नए ट्राउट रेसवेज के निर्माण, 33000 टन मत्स्य उत्पादन और 80 लाख वार्षिक ट्राउट मत्स्य बीज उत्पादन के लक्ष्य को समय से पूरा करने के निर्देश दिये।



उत्तराखंड में मेडिकल छात्रों को डिजी लॉकर से मिलेंगी डिग्रियाँ

चर्चा में क्यों ?

17 जून, 2023 को उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि उच्च शिक्षा की तर्ज पर अब प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस छात्र-छात्राओं को डिजी लॉकर के माध्यम से डिग्रियाँ व अन्य शैक्षिक प्रमाण-पत्र मिलेंगे। इस संबंध में उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय को शीघ्र डिजी लॉकर के लिये सिस्टम तैयार करने के निर्देश दिये गए हैं।

प्रमुख बिंदु

- इसके अलावा प्रदेश के सभी अस्पताल व स्वास्थ्य केंद्र एक रंग में नजर आएंगे। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को कलर कोड तय करने को कहा गया है, जिससे सभी चिकित्सा इकाइयों में एकरूपता देखने को मिल सके।

- बैठक में बताया गया कि मेडिकल छात्र-छात्राओं के शैक्षिक प्रमाण-पत्र डिजी लॉकर पर उपलब्ध होंगे, जिससे कभी भी मेडिकल छात्र अपनी डिग्री और अन्य शैक्षिक प्रमाण-पत्र डाउनलोड कर सकें।
- स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा का डिजिटलीकरण करते हुए राजकीय मेडिकल कॉलेजों व नर्सिंग कॉलेजों को ई-ग्रंथालय पोर्टल से जोड़ा जाएगा, जिससे मेडिकल के छात्र-छात्राओं को किताबों की कमी से न जूझना पड़े।
- ई-ग्रंथालय पोर्टल पर छात्र-छात्राओं को पाठ्यक्रम संबंधी पुस्तक के अलावा शोधपत्र भी ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा छात्रों को देश-विदेश के मेडिकल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों से भी जुड़ने का अवसर मिलेगा।
- राज्य में अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में रोगी पंजीकरण शुल्क की दर एक समान की जाएगी। इसके लिये शीघ्र प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जाएगा।



प्रदेश के खेल प्रशिक्षकों का मानदेय 15 हजार से बढ़ाकर 48 हजार करने की तैयारी

चर्चा में क्यों ?

17 जून, 2023 को उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य ने देहरादून निदेशालय में हुई खेल विभाग की समीक्षा बैठक में खेल विभाग में संविदा पर कार्यरत खेल प्रशिक्षकों का मानदेय भारतीय खेल प्राधिकरण की तर्ज पर 15 हजार से बढ़ाकर न्यूनतम 48 हजार रुपए करने की तैयारी का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये।

प्रमुख बिंदु

- खेल मंत्री ने कहा कि राज्य में कुछ खेल प्रशिक्षक पीआरडी जवानों से भी कम मानदेय पा रहे हैं। विभाग को पर्याप्त और अच्छे खेल प्रशिक्षक मिल सकें, इसके लिये साई की तर्ज पर इनका मानदेय बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है।
- विदित है कि प्रदेश में लगभग 200 खेल प्रशिक्षक संविदा पर हैं। खासकर पर्वतीय जिलों में इनकी पिछले काफी समय से कमी है। इसकी एक वजह इनका बहुत कम मानदेय है।

- साई में खेल प्रशिक्षक को न्यूनतम 48 हजार रुपए मानदेय दिया जा रहा है। विभिन्न श्रेणियों के हिसाब से मानदेय दिया जाता है। इसी तरह खेल विभाग में भी मानदेय बढ़ाया जाएगा, लेकिन मानदेय के लिये जो अर्हता साई की है, वही अर्हता होनी चाहिये।



प्रदेश में होगा आपदा प्रबंधन पर विश्व कॉन्ग्रेस का आयोजन

चर्चा में क्यों ?

17 जून, 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि छठवें वैश्विक सम्मेलन 'आपदा प्रबंधन पर छठवीं विश्व कॉन्ग्रेस' का आयोजन देहरादून में 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक होना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने इस छठवें वैश्विक सम्मेलन की विवरणिका का विमोचन भी किया।

प्रमुख बिंदु

- उत्तराखंड में होने वाली इस आपदा प्रबंधन कॉन्ग्रेस का विषय 'STRENGTHENING CLIMATE ACTION & DISASTER RESILIENCE' है। इस विश्व कॉन्ग्रेस में आपदा प्रबंधन के लिये नवाचार, सहयोग एवं संचार पर प्रमुखता से चिंतन एवं मंथन होगा।
- इसके अलावा पर्वतीय पारिस्थितिकी एवं संचार पर विशेष रूप से फोकस किया जाएगा। वैश्विक स्तर पर होने वाली इस कार्यशाला से उत्तराखंड को नई पहचान मिलेगी।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि आपदा न्यूनीकरण कैसे किया जाए, यह हिमालयी राज्यों की बड़ी जरूरत है। सम्मेलन में विशेषज्ञों की ओर से आपदा न्यूनीकरण, जन-धन की हानि कैसे कम-से-कम हो और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रयोग पर गहनता से विचार-विमर्श किया जाएगा।
- कई कारणों से नदियाँ जब रास्ता बदलती हैं, तो इससे भी काफी जन-धन की हानि होती है। इस पर भी सम्मेलन में विशेषज्ञों द्वारा चर्चा की जाएगी।



प्रदेश की आठ शख्सियतों को रक्षामंत्री ने किया सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

19 जून, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार अमर उजाला उत्तराखंड संवाद कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रदेश की आठ शख्सियतों को सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- इन हस्तियों को अपनी सोच, प्रतिभा, लगन, मेहनत के दम पर कुछ अलग करके राज्य का नाम राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय फलक पर रोशन करने के लिये कार्यक्रम में सम्मानित किया गया।
- विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित शख्सियतें-
 - ◆ श्रेणी- उदीयमान प्रतिभा
 - राहुल रावत (कोटद्वार निवासी दिगंतरा कंपनी के संस्थापक) : नवाचार, पर्यावरण, कला-संस्कृति क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका निभाने के लिये इन्हें यह पुरस्कार मिला।
 - हेमलता कबडवाल (मुक्तेश्वर निवासी चित्रकार) : नए संसद भवन में इनकी बनाई ऐपण कला को स्थान मिला। कला-संस्कृति क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिये इन्हें यह पुरस्कार मिला।
 - दिव्या नेगी (टिहरी निवासी युवा वक्ता) : राष्ट्रीय युवा संसद में जी-20 पर भारत की भूमिका पर शानदार प्रस्तुति दी। कला-संस्कृति क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिये इन्हें यह पुरस्कार मिला।
 - बबीता रावत (रुद्रप्रयाग निवासी किसान) : इन्होंने 37 हजार वर्ग फीट भूमि हल चलाकर सब्जी, मशरूम उत्पादन किया। नवाचार, पर्यावरण, कला-संस्कृति क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिये इन्हें यह पुरस्कार मिला।
 - शिकायना मुखिया (देहरादून निवासी युवा गायिका) : इन्होंने बॉलीवुड जगत में अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा। नवाचार, पर्यावरण, कला-संस्कृति क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिये इन्हें यह पुरस्कार मिला।
 - रजत जैन-अर्पित जैन (देहरादून निवासी इनोवेटर) : इन्होंने दुनिया की सबसे छोटी ईसीजी मशीन बनाई। नवाचार, पर्यावरण, कला-संस्कृति क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिये इन्हें यह पुरस्कार मिला।
 - ◆ श्रेणी- संस्कृतिकर्मी
 - बॉबी कैश (देहरादून निवासी गायक-संगीतकार) : इन्होंने देश-विदेश में अपनी आवाज़ की धूम मचाई। संगीत साधना व कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिये इन्हें यह पुरस्कार मिला।
 - ◆ श्रेणी- सामाजिक कृतज्ञता
 - प्रभा देवी सेमवाल (रुद्रप्रयाग निवासी पर्यावरण रक्षक) : इन्होंने बंजर भूमि पर खुद का जंगल उगाया। सामाजिक सरोकार व पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिये इन्हें यह पुरस्कार मिला।



मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के नए पटेल भवन का किया उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

20 जून, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के पुलिस विभाग के नए सरदार पटेल भवन का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने पुलिस का ई-बीट एप भी लॉन्च किया। वहीं पुलिस ट्रेनिंग के नए पाठ्यक्रम का भी विमोचन किया गया।
- उन्होंने बताया कि पुलिस के आवास और कार्यालय बढ़ाने के लिये जल्द कदम उठाए जाएंगे। उत्तराखंड पुलिस का आवास प्रतिशत 18 फीसदी है, जो कि बहुत कम है। इसे जल्द से जल्द बढ़ाया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीम में उत्तराखंड अब सबसे आगे निकल रहा है। राज्य सरकार को आने वाले 25 सालों को लेकर योजना बनानी होगी। पुलिस को भी इसी हिसाब से तैयार रहना होगा।



प्रदेश के लिये ओडिशा में लगेगा कोयले से बिजली का प्लांट

चर्चा में क्यों ?

21 जून, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में बिजली की मांग के सापेक्ष उत्पादन काफी कम होने के चलते अब ओडिशा में कोयले से बिजली पैदा की जाएगी। इसके लिये प्रदेश में जल्द ही टीएचडीसी-यूजेवीएनएल का संयुक्त उपक्रम बनने जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- इस प्रोजेक्ट के बनने से अगले चार से पाँच साल में प्रदेश में बिजली किल्लत पर काबू पाया जा सकेगा।
- ऊर्जा सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि जल विद्युत परियोजनाओं से होने वाला बिजली उत्पादन सीजन के हिसाब से प्रभावित होता है। मानसून आता है तो उत्पादन बढ़ता है, लेकिन नदियों में गाद आने पर कम होता है। सर्दियों और इसके बाद गर्मियों में नदियों का जल स्तर गिरने से उत्पादन कम हो जाता है।
- दूसरी ओर सौर ऊर्जा परियोजनाओं से होने वाला उत्पादन भी केवल दिनभर का होता है। रात को इसका इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि अभी ऐसी बैटरी नहीं है, जो कि इस बिजली को स्टोर कर सके।
- प्रदेश में बिजली की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। जिसको ध्यान में रखते हुए थर्मल पावर प्लांट के बारे में सोचा जा रहा है। पूर्व में सरकार तय कर चुकी है कि कोयले से बिजली बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसके लिये जल्द ही टीएचडीसी-यूजेवीएनएल का संयुक्त उपक्रम बनाया जाएगा।

- ओडिशा में टीएचडीसी के पास पहले से ही कोयले की खदान है। इसके पास ही संयंत्र स्थापित किया जाएगा, क्योंकि वहाँ से उत्तराखंड तक कोयला पहुँचाने का खर्च काफी अधिक होगा।
- ऊर्जा सचिव ने बताया कि टीएचडीसी पहले से ही अपना संयंत्र बनाने की तैयारी में था, जो कि अब उत्तराखंड के साथ संयुक्त तौर पर बनेगा। अगले चार से पाँच साल में ये बन जाएगा तो राज्य में बिजली किल्लत काबू में आ जाएगी।
- प्रदेश में तीन गैस आधारित पावर प्लांट हैं। इनमें से दो चल रहे हैं, जबकि तीसरे में कुछ निर्णय होने हैं। तीसरे प्लांट पर भी जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद गैस ऊर्जा संयंत्र से बिजली उत्पादन बढ़ जाएगा।



प्रदेश में हर वाइब्रेंट विलेज में बनेगा हेलीपैड

चर्चा में क्यों ?

21 जून, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के सीमांत जिलों में प्रत्येक वाइब्रेंट विलेज में हेलीपैड बनाया जाएगा। साथ ही इन गांवों में ब्रेकफास्ट टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- जानकारी के अनुसार मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने उत्तरकाशी और चमोली के जिलाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योजना बनाने के निर्देश दिए।
- राज्य सचिवालय में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि जिलाधिकारी अपने जिलों में वाइब्रेंट विलेज में जाकर देखें कि किन-किन सेवाओं की सख्त आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेज के तहत क्षेत्र में अटल स्कूलों की शुरुआत की जाए। पर्यटन की दृष्टि से इन गांवों में और क्या-क्या गतिविधियां शुरू की जा सकती हैं, इस दिशा में भी कार्य किया जाए।
- उन्होंने वाइब्रेंट विलेज के लिये योजनाओं को प्राथमिकता पर लेने के निर्देश देते हुए कहा कि इन गांवों में बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल आदि की उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए।
- मुख्य सचिव ने कहा कि इन गाँवों के लिये योजनाएँ इस प्रकार से तैयार की जाएँ कि स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके। इन क्षेत्रों में बुयाल और ट्रेकिंग रूट्स को विकसित कर क्षेत्रवासियों को रोजगार से जोड़ा जा सकता है। उन्होंने कौशल विकास विभाग को, क्षेत्र के युवाओं को कई ट्रेड्स में निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने के भी निर्देश दिये।



राष्ट्रपति ने सैन्य नर्सिंग सेवा की मेजर जनरल स्मिता देवरानी और ब्रिगेडियर अमिता देवरानी को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया

चर्चा में क्यों ?

22 जून, 2023 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु, जो सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर हैं, ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में सैन्य नर्सिंग सेवा (एमएनएस) की अपर महानिदेशक (एडीजी) मेजर जनरल स्मिता देवरानी और दक्षिणी कमान मुख्यालय ब्रिगेडियर एमएनएस, ब्रिगेडियर अमिता देवरानी को क्रमशः वर्ष 2022 एवं 2023 के लिये राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने समारोह में वर्ष 2022 एवं 2023 के लिये कुल 30 नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया है।
- उत्तराखंड के कोटद्वार जिले की रहने वाली देवरानी बहनों को दिया गया पुरस्कार उनके लगभग चार दशकों के उल्लेखनीय योगदान और सेवा के लिये एक उपयुक्त सम्मान है।
- इनके अलावा राष्ट्रपति ने उत्तराखंड की ही मंजू कैरा को वर्ष 2022 के लिये राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया।
- विदित है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1973 में संस्थापित राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार नर्सों और नर्सिंग प्रोफेशनलों को समाज को प्रदान की गई उनकी सराहनीय सेवाओं के सम्मानस्वरूप दिया जाता है।
- मेजर जनरल स्मिता देवरानी को 1983 में एमएनएस में कमीशन किया गया था। 01 अक्टूबर, 2021 को एडीजी एमएनएस का कार्यभार सँभालने से पूर्व, वह आर्मी हॉस्पिटल (रिसर्च एंड रेफरल) की प्रिंसिपल मैट्रन, ब्रिगेडियर एमएनएस, मुख्यालय (मध्य कमान); प्रिंसिपल मैट्रन, कमांड हॉस्पिटल (दक्षिणी कमांड) और निदेशक एमएनएस (प्रशासन) जैसी विभिन्न प्रमुख नैदानिक, कर्मचारी और प्रशासनिक पदों पर रहीं।
- ब्रिगेडियर अमिता देवरानी को 1986 में सेवा में कमीशन किया गया था। उन्होंने 01 सितंबर, 2021 को दक्षिणी कमान के ब्रिगेडियर एमएनएस का अपना वर्तमान पदभार ग्रहण किया। इससे पूर्व, उन्होंने पुणे के सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ नर्सिंग; आर्मी हॉस्पिटल, रिसर्च एंड रेफरल कॉलेज ऑफ नर्सिंग और इंडियन नेवल हॉस्पिटल शिप (आईएनएचएस) अश्विनी के कॉलेज ऑफ नर्सिंग की वाइस प्रिंसिपल जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है।



मुख्यमंत्री धामी ने किया करपात्री महाराज वेदशास्त्र अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

22 जून, 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय से वर्चुअल माध्यम से देवप्रयाग स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर में स्वामी करपात्री महाराज की स्मृति में वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- वर्चुअल उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र ने राज्य सरकार को यह बड़ी सौगात दी है जो देववाणी संस्कृत के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने करपात्री महाराज के नाम से केंद्र बनाए जाने पर कहा कि इससे परिसर का महत्त्व बढ़ेगा।
- विदित है कि धर्मसम्राट स्वामी करपात्री भारत के एक संत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं राजनेता थे। इनका जन्म सन् 1907 ईस्वी में श्रावण मास, शुक्ल पक्ष द्वितीया को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के भटनी ग्राम में सनातनधर्मी सरयूपारीण ब्राह्मण रामनिधि ओझा एवं श्रीमती शिवरानी जी के आँगन में हुआ।
- बचपन में उनका नाम 'हरि नारायण' रखा गया। वे दशनामी परंपरा के संन्यासी थे। दीक्षा के उपरांत उनका नाम 'हरिहरानंद सरस्वती' था किंतु वे 'करपात्री' नाम से ही प्रसिद्ध थे, क्योंकि वे अपनी अंजुलि का उपयोग खाने के बर्तन की तरह करते थे (कर = हाथ, पात्र = बर्तन, करपात्री = हाथ ही बर्तन हैं जिसके)।
- उन्होंने 'अखिल भारतीय राम राज्य परिषद' नामक राजनैतिक दल भी बनाया था। धर्मशास्त्रों में इनकी अद्वितीय एवं अतुलनीय विद्वत्ता को देखते हुए इन्हें 'धर्मसम्राट' की उपाधि प्रदान की गई।
- स्वामी करपात्री महाराज ने 1940 में जबरन मुसलमान बनाए गए लोगों को फिर से हिंदू बनाया था। 1966 में करपात्री महाराज ने तत्कालीन सरकार के खिलाफ गौ संवर्धन को लेकर आंदोलन शुरू किया था।
- 7 फरवरी, 1982 को केदारघाट वाराणसी में स्वेच्छा से उनके पंच प्राण महाप्राण में विलीन हो गए। उनके निर्देशानुसार उनके नश्वर पार्थिव शरीर का केदारघाट स्थित श्री गंगा महारानी को पावन गोद में जल समाधि दी गई।



उत्तराखंड मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम

चर्चा में क्यों ?

24 जून, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में आपदाओं से बचाव के लिये उत्तराखंड मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम के नाम से इस पायलट प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में 250 जगहों पर सायरन सिस्टम लगाया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- उत्तराखंड में स्थापित किये जाने वाले इस प्रोजेक्ट के लिये प्रथम चरण में 118 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है।
- विदित है कि बीते दिनों मुख्य सचिव एसएस संघु की अध्यक्षता में हुई उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) की बैठक में प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की जा चुकी है।
- इस परियोजना को वर्ल्ड बैंक फंडिंग कर रहा है। अब इसके लिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल टेंडर आमंत्रित किये जाएंगे।
- इस परियोजना के लागू होने के बाद उत्तराखंड, केरल के बाद दूसरा राज्य होगा, जो इस प्रणाली को अपनाने जा रहा है। केरल ने अपने यहाँ इस प्रोजेक्ट पर करीब 80 करोड़ रुपए खर्च किये हैं।
- अर्ली वार्निंग सायरन सिस्टम के तहत राज्य में संवेदनशील स्थानों पर स्थित मोबाइल टावरों पर यह सिस्टम लगाया जाएगा। जहाँ मोबाइल टावर नहीं होंगे, वहाँ नए टावर लगाए जाएंगे।
- इसके बाद भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) और सेंटर वाटर कमीशन जैसी संस्थाओं से प्राप्त होने वाले अलर्ट को सायरन के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया जाएगा। बाढ़, भूस्खलन, भूकंप, अतिवृष्टि, हिमस्खलन जैसी आपदाओं में लोग वक्त रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुँचकर जान-माल की सुरक्षा कर सकेंगे।
- किसी भी आपदा की स्थिति में तीन स्तरों से सायरन सिस्टम को ऑपरेट किया जा सकेगा। पहला, जहाँ सायरन सिस्टम लगेगा, वहाँ एक मिनी कंट्रोल रूम भी होगा।
- दूसरा, जिला स्तर पर बने कंट्रोल रूम से भी इसे ट्रिगर (बटन दबाना) किया जा सकेगा और तीसरा, राज्य स्तर पर बने कंट्रोल रूम से भी सायरन सिस्टम को एक्टिवेट किया जा सकेगा।
- टीएचडीसी (टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन) की ओर से ऋषिकेश में गंगातटों पर सायरन सिस्टम लगाया गया है, लेकिन यह तभी काम करता है, जब बांध से पानी छोड़ा जाता है। मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम हर प्रकार की आपदा में चेतावनी सायरन जारी करेगा।
- उत्तराखंड मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम की खास बात यह है कि यह अलग-अलग आपदाओं में अलग-अलग प्रकार की ध्वनियाँ प्रसारित करेगा। इसके लिये आमजन को पहले ही बता दिया जाएगा कि किस आपदा में सायरन कैसी ध्वनि प्रसारित करेगा। इससे लोगों को पता चल सकेगा कि वह किस तरह के खतरे में हैं।
- सायरन सिस्टम लगाने के लिये जिलों से मोबाइल टावरों की सूची मांगी गई है। प्रोजेक्ट को एचपीसी और वर्ल्ड बैंक पहले ही मंजूरी दे चुका है। पहले चरण में सायरन की संख्या 250 फिर अगले चरण में 1000 की जाएगी।

उत्तराखंड में साल के बीज लाएंगे समृद्धि, वनोपज में जुड़ा नया अध्याय

चर्चा में क्यों ?

25 जून, 2023 को उत्तराखंड वन विभाग के मुख्य वन संरक्षक मनोज चंद्रन ने बताया कि प्रदेश में पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के रूप में साल के बीजों को इकट्ठा कर बाजार में बेचने की योजना पर काम किया जा रहा है। इस तरह से वन बाहुल्य प्रदेश उत्तराखंड में वनोपज का नया अध्याय जुड़ गया है।

प्रमुख बिंदु

- प्रदेश में करीब पाँच हजार वर्ग किमी. क्षेत्रफल में फैले साल के जंगल ग्रामीणों और वन विभाग की आय का नया जरिया बनेंगे। प्रदेश में धामी सरकार का जोर वनों से आय बढ़ाने पर है।
- इसके लिये इको टूरिज्म के अलावा वनों से मिलने वाली विभिन्न प्रकार की उपज से कैसे समृद्धि लाई जा सकती है, इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से अधिकारियों को निर्देश दिये गए हैं। इसी कड़ी में वन विभाग ने साल के बीजों से आय जुटाने की इस योजना पर पहली बार काम शुरू किया है।
- एक अनुमान के अनुसार उत्तराखंड में करीब 45 लाख कुंतल साल के बीजों का उत्पादन होता है। हालांकि इस योजना में सभी बीजों को इकट्ठा नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके लिये फायर लाइन और सड़कों के किनारे गिरे बीजों को इकट्ठा किया जाएगा। इस हिसाब से लाखों कुंतल बीज इकट्ठा हो जाएंगे।

- आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में हजारों वर्षों से पित्त, ल्यूकोरिया, गोनोरिया, त्वचा रोग, पेट संबंधी विकार, अल्सर, घाव, दस्त और कमजोरी के इलाज में साल के बीज का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा, चॉकलेट बनाने में भी साल के बीजों का प्रयोग किया जाता है।
- साल के बीजों से बहुमूल्य खाद्य तेल निकाला जाता है। बीज में 19.20 प्रतिशत तेल होता है। तेल का उपयोग मक्खन के विकल्प के रूप में और मिष्ठान्न तथा खाद्य पदार्थों में भी किया जाता है। तेल निकालने के बाद बची खली में 10.12 प्रतिशत प्रोटीन होता है। इसका उपयोग मुर्गियों के चारे के रूप में किया जाता है।
- देश में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड ऐसे राज्य हैं, जहाँ बड़े पैमाने पर साल के बीजों को प्रमुख वनोपज के तौर पर लघु वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से इकट्ठा करवाया जाता है। इन राज्यों में साल के बीजों का हर साल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) भी जारी किया जाता है।

नशा मुक्ति केंद्रों के संचालन लिये बनेगा एक्ट, केंद्र सरकार ने दी अनुमति

चर्चा में क्यों ?

26 जून, 2023 को उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार नशा मुक्ति केंद्रों को अब नियमों के दायरे में बांधने की तैयारी कर रही है। इस कड़ी में प्रदेश में जल्द ही 'मेंटल हेल्थ केयर एक्ट' लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद प्रदेश सरकार इसके प्रारूप को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। इसे जल्द ही कैबिनेट में रखने की तैयारी है।
- 'मेंटल हेल्थ केयर एक्ट' के तहत मानसिक स्वास्थ्य केंद्र व संस्थानों को राज्य मेंटल हेल्थ केयर अथारिटी में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। एक्ट का उल्लंघन करने वालों पर 50 हजार से लेकर दो लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
- विदित है कि प्रदेश में अभी नशा मुक्ति केंद्रों के संचालन को लेकर कोई निश्चित मानक नहीं बने हैं। जिलाधिकारी अपने-अपने स्तर से इनके संचालन को गाइडलाइन जारी करते हैं। यद्यपि इस प्रकार की गाइडलाइन को नशा मुक्ति संचालक हाईकोर्ट में चुनौती दे देते हैं। उनका तर्क यह रहता है कि इस तरह की गाइडलाइन उन पर सीधे लागू नहीं होती।
- दरअसल, प्रदेश में नशा मुक्ति केंद्रों के संचालन को लेकर सवाल उठते रहे हैं। सही प्रकार के भवन न होने, चिकित्सकों की तैनाती और प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ की कमी के कारण भी मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों की कार्यशैली पर सवाल उठते रहे हैं।
- यहाँ मरीजों का सही प्रकार से इलाज न करने और उनको प्रताड़ित करने की बातें भी सामने आई हैं। यहाँ तक कि कई बार मरीजों के मौत की बात भी सामने आई है। इसे देखते हुए प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों के संचालन को एक्ट के दायरे में लाने की बात चल रही है। इस कड़ी में प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र भेजकर प्रदेश में अपना मेंटल हेल्थ केयर एक्ट लाने के लिये अनुमति देने का अनुरोध किया था, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है।

प्रदेश में अब इजराइली कृषि तकनीक से होगी बागवानी

चर्चा में क्यों ?

27 जून, 2023 को देहरादून स्थित राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से.नि.) की अध्यक्षता में इंडो-इजराइल कृषि परियोजना की बैठक हुई, जिसमें बताया गया कि प्रदेश में इजराइल की कृषि तकनीक से बागवानी को बढ़ावा दिया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- इसके लिये इंडो-इजराइल कृषि परियोजना के तहत राज्य में उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी) स्थापित किया जाएगा। इजराइल के पास ड्राई लैंड फार्मिंग की तकनीक है, जिसमें पानी का कम इस्तेमाल कर फसलों का अधिक उत्पादन किया जाता है।
- बैठक में राज्यपाल ने कहा कि राज्य में इजराइली तकनीकी के लिये रोड मैप तैयार कर मिशन मोड में काम करने की आवश्यकता है। इसके लिये उद्यान विभाग और पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की ओर से योजना बनाई जाए।

- उन्होंने इंडो-इजराइल प्रतिनिधियों को उत्तराखंड की केदारघाटी का शहद प्रतीकात्मक रूप मंष भेंट किया।
- उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि भारत और इजराइल कृषि परियोजना का लक्ष्य फसल विविधता को बढ़ावा देने के साथ कम पानी के प्रयोग से उत्पादकता बढ़ाना है। इजराइल कृषि प्रौद्योगिकी पर आधारित उत्कृष्टता केंद्र से राज्य में बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ेगा। इसका लाभ किसानों को मिलेगा।
- कृषि तकनीक को सीखने के लिये उत्तराखंड का एक दल जल्द ही इजराइल जाएगा।
- इजराइल एंबेसी से आए येअर इशेल ने बताया कि इंडो-इजराइल कृषि परियोजना के तहत 24 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किये जा चुके हैं। राज्य के मैदानी व घाटी क्षेत्रों में बागवानी की संभावनाओं को देखते हुए उत्तराखंड में भी सेंटर बनाया जाएगा। इसमें पंतनगर विश्वविद्यालय का सहयोग लिया जाएगा।

टिहरी गढ़वाल में जी-20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक संपन्न

चर्चा में क्यों ?

28 जून, 2023 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के नरेंद्रनगर में तीन दिवसीय जी-20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप (आईडब्ल्यूजी) की तीसरी बैठक संपन्न हुई।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की अगली और आखिरी बैठक 19-20 सितंबर, 2023 को खजुराहो (मध्य प्रदेश) में आयोजित होगी।
- उल्लेखनीय है कि तीन दिवसीय आईडब्ल्यूजी बैठक 26 जून को टिहरी गढ़वाल के नरेंद्रनगर स्थित होटल वेस्टिन रिजॉर्ट में शुरू हुई थी, जिसमें जी-20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के लगभग 63 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
- बैठक में पहले दिन भविष्य के शहरों के मूलभूत ढाँचागत विकास पर चर्चा की गई।
- एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एआईआईबी की ओर से आयोजित रहने योग्य शहर बनाने पर उच्च स्तरीय सेमिनार में सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भविष्य के शहरों में निजी निवेश को बढ़ाने, नीतियों को सरल बनाने और मजबूत ढाँचागत विकास को बढ़ावा देने के विषयों पर चर्चा की।
- इसके अलावा प्राकृतिक चुनौतियों से लड़ने के लिये आपसी सामंजस्य पर बल दिया।
- बैठक के दूसरे दिन पहले सत्र में समावेशी शहरों को सक्षम बनाने, पहुँच बढ़ाने और शहरी सेवाओं में अवसर विषय पर चर्चा की गई। इसमें प्रतिनिधियों ने बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढाँचा निवेश संकेतक लागू करने के तरीकों पर विचार-विमर्श किया।
- अंतिम दिन आयोजित इस बैठक में दो सत्रों में प्रतिनिधियों ने शहरी प्रशासन की क्षमताओं को बढ़ाने के ढाँचे के साथ-साथ 2023 इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंडा में उल्लेखित एक और महत्वपूर्ण कार्यधारा पर चर्चा की।
- इस सत्र में जी-20 देशों के बुनियादी ढाँचे के बजट आवंटन का विश्लेषण भी किया गया तथा जी-20 की ओर से निर्धारित क्यूआईआई संकेतक पर विस्तृत चर्चा हुई।
- इसके अलावा, केंद्र सरकार के नागरिक विमानन मंत्रालय की ओर से 'भारत को एमआरओ हब बनाने पर गोलमेज सम्मेलन' आयोजित किया गया।
- तीन दिन विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा को सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने सार्थक बताया, जिसमें प्रेसीडेंसी ने स्पष्ट रूप से परिभाषित परिणामों की रूपरेखा तैयार की।



प्रदेश के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्थापित होंगे वेदर स्टेशन

चर्चा में क्यों ?

27 जून, 2023 को उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव डॉ. रंजीत सिन्हा ने बताया कि उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भूसूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान (डीजीआई) चंडीगढ़ वेदर स्टेशन स्थापित करेगा, जिसका खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी।

प्रमुख बिंदु

- उत्तरकाशी में हिमस्खलन की घटना से सबक लेने के बाद हिमालय के सीमांत क्षेत्रों में भी वेदर स्टेशन स्थापित किये जाने का फैसला लिया गया है।
- इससे हिमस्खलन होने से पहले ही इसके संकेत मिल जाएंगे। इसके लिये उच्च हिमालयी क्षेत्रों में 74 वेदर स्टेशन स्थापित किये जाएंगे।
- विदित है कि जलवायु परिवर्तन के चलते बीते कुछ सालों में उत्तराखंड में हिमस्खलन की घटनाएँ बढ़ी हैं। यह बेहद खतरनाक पैटर्न है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में बड़ी चिंता की वजह बना हुआ है।
- बीते वर्ष अक्टूबर में उत्तरकाशी जिले में उच्च हिमालयी क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिये निकले नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के 29 प्रशिक्षु पर्वतारोही डोकराणी बामक ग्लेशियर में हिमस्खलन की चपेट में आ गए थे। इनमें से 27 की मौत हो गई थी।
- हालाँकि प्रदेश में हिमस्खलन के कारण मौतों की यह पहली घटना नहीं थी, इससे पहले भी इस तरह की घटनाओं में कई बार जान-माल की हानि हुई है, लेकिन इस घटना से सबक लेते हुए प्रदेश सरकार ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) को इस दिशा में ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिये थे।
- यूएसडीएमए के अधिकारियों ने बताया कि अभी तक मौसम संबंधी जो डाटा हमें प्राप्त हो रहा है, उसमें हिमस्खलन जैसी घटनाओं की सटीक जानकारी नहीं मिल पाती है। इसलिये उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हिमस्खलन को ध्यान में रखते हुए अलग से वेदर स्टेशन स्थापित करने का फैसला लिया गया है। ताकि सटीक आँकड़ों के साथ अलर्ट जारी किया जा सके। यह स्टेशन कहाँ-कहाँ स्थापित किये जाएंगे, सुरक्षा की दृष्टि से इसका खुलासा नहीं किया गया है।
- उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने की दिशा में यह बहुत बड़ा कदम है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में वेदर स्टेशन स्थापित होने के बाद हमें सटीक आँकड़े प्राप्त हो पाएंगे, जिससे सही समय पर अलर्ट जारी कर जान माल के नुकसान को कम किया जा सकेगा।

नोट :

- वर्ष 2000 के बाद उत्तराखंड में हिमस्खलन की प्रमुख घटनाएँ:
 - ◆ वर्ष 2022 में उत्तरकाशी में डोकराणी बामक ग्लेशियर में हिमस्खलन की चपेट में आने से 27 प्रशिक्षु पर्वतारोहियों की मौत।
 - ◆ वर्ष 2021 में त्रिशूल चोटी आरोहण के दौरान हिमस्खलन की चपेट में आए नौसेना के पाँच पर्वतारोहियों सहित छह की मौत।
 - ◆ वर्ष 2021 में लंखागा दर्रे में हिमस्खलन से नौ पर्यटकों की मौत।
 - ◆ वर्ष 2019 में नंदादेवी चोटी के आरोहण के दौरान हिमस्खलन की चपेट में आने से चार विदेशी पर्वतारोही सहित आठ की मौत।
 - ◆ वर्ष 2016 में शिवलिंग चोटी पर दो विदेशी पर्वतारोहियों की मौत।
 - ◆ वर्ष 2012 में सतोपंथ ग्लेशियर पर क्रेवास में गिरकर आस्ट्रेलिया के एक पर्वतारोही की मौत।
 - ◆ वर्ष 2012 में वासुकीताल के पास हिमस्खलन से बंगाल के पाँच पर्यटकों की मौत।
 - ◆ वर्ष 2008 में कालिंदीपास में हिमस्खलन से बंगाल के तीन पर्वतारोही और पाँच पोर्टर की मौत।
 - ◆ वर्ष 2005 में सतोपंथ चोटी पर आरोहण के दौरान हिमस्खलन से सेना के एक पर्वतारोही की मौत।
 - ◆ वर्ष 2005 में चौखंभा में हिमस्खलन से पाँच पर्वतारोहियों की मौत।
 - ◆ वर्ष 2004 में कालिंदीपास में हिमस्खलन से चार पर्वतारोहियों की मौत।
 - ◆ वर्ष 2004 में गंगोत्री-टू चोटी में हिमस्खलन से बंगाल के चार पर्वतारोहियों की मौत।

प्रदेश में दो नए शहरों को बसाने का रास्ता साफ

चर्चा में क्यों ?

27 जून, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में किच्छा के निकट पराग फार्म व डोईवाला के निकट दो नए शहर बसाने को केंद्र सरकार ने प्रारंभिक तौर पर हरी झंडी दिखा दी है।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि दो नए शहर बसाने के संबंध में राज्य सरकार से जो जानकारियाँ मांगी गई थीं, वह केंद्र को उपलब्ध कराई जा चुकी हैं, जिसके बाद जल्द ही इन दोनों शहरों को बसाने के लिये केंद्र की मंजूरी मिल सकती है।
- उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र से इस संबंध में अनुरोध करते हुए 1100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया था। इनमें एक शहर प्रदेश के उधमसिंह नगर जिले के किच्छा के निकट पराग फार्म की भूमि पर इंडस्ट्रियल सिटी के नाम से 378.50 हेक्टेयर भूमि पर बनेगा।
- इसके अलावा दूसरी टाउनशिप, डोईवाला के निकट दून-हरिद्वार हाईवे पर एयरो सिटी के नाम से बनेगी। इंटीग्रेटेड टाउनशिप के नाम से यह शहर 3080.8 भूमि पर बनाया जाएगा। इसमें 746.98 हेक्टेयर सरकारी भूमि और 2333.81 हेक्टेयर निजी भूमि होगी।
- आवास विभाग इन सभी शहरों में सुविधाएँ देगा। इनमें सड़क, सीवर से लेकर अत्याधुनिक शहरों जैसी सभी सुविधाएँ शामिल होंगी।
- टाउन प्लानिंग विभाग की मदद से इन शहरों का मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। इसी हिसाब से निजी सहभागिता से शहरों को बनाने का काम होगा। सरकार इनमें कुछ अपनी जमीन भी देगी।